

क्रिस्तु नीति निर्देशन-त्त्वों की आलोचना भी की गई है।
वैधानिक शक्ति का अभाव - अर्थात् इन न्यायालयों के
विस्तार नहीं किया जा सकता है। के. ए. हीयलन-इहे,
उद्देश्यों एवं आकांक्षों का धीरे-धीरे अभाव है।

अल्पसंख्यक तथा अल्पसंख्यक - निर्देशन-त्त्वों में वर्णित कुछ
के विषय अल्पसंख्यक तथा अल्पसंख्यक हैं - जैसे - समाजवादी
लक्ष्यों के मूल्यों तथा मूल्यों के अपनी धारणाओं-
पर के कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है।

राजनीतिज्ञों की स्वार्थ-लालि - यह गरीब जनता को
अपने पक्ष में खिंचे है

इसमें कम तथा शिक्षा, जैसे शिक्षण जैसे अधिकार नहीं
दिए गए हैं।
अध्यक्ष - जैसे न्यायनिपेक्षकों का अभाव है जो
सबू नहीं हो सका।

क्रिस्तु इनके वास्तविक ही लक्ष्यों का महत्व भी है -

यह सत्ता-सूत्र दल के लिए आचार लोहता का काम-कला
है। क्योंकि नैतिक सत्ता-सूत्र दल है - वह अपने अधिकार-
की अवहेलना नहीं कर सकता है।

यह वास्तविक लोकतंत्र का विरुद्ध दिशा है - अधिक
संभव के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं है। यह
निर्देशन-त्त्व हैं एक लोक-प्रजापति राज्य की स्थापना
करता है जिनमें अधिक तथा सामाजिक लोकतंत्र का भी समावेश
है। यह लक्ष्य की स्थापना का मापदण्ड भी है।

यह उपयोगी नैतिक आदेश है।

यह लक्ष्य-मासिक न्यायालयों के निर्देशन है। अपने
पक्षों के न्यायालयों के इन्हें स्थापित दिया है।

हीनलपवाद के शब्दों के " राजनीति के इस मूल्य लक्ष्यों
का वैधानिक प्रभाव न हो सके इनके द्वारा न्यायालयों
के लिए उपयोगी प्रकार-स्वरूप का कार्य किया जाता है। "

निर्देशक विद्यालयों का क्रियान्वयन सरकार ने इन नीति-निर्देशक विद्यालयों को लागू करने के प्रयास-क्रिये हैं -

- संविधान लागू होने के बाद ही सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर श्रम, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी व कार्य के विद्यालयों को बढ़ाए तथा राष्ट्रीय-आय तथा लोगों के रहन-सहन को ध्यान में रखकर उनको प्रयास किए गए हैं।

- क्रियाशील राज्य की आधिपत्य, क्रियाशील शक्ति आदिना आदि द्वारा सुवर्ण वर्ग एवं क्रियाशील वर्गों की शोषण-लेटका का काबू बंधा -

- दुआदत को दूर करने का प्रयास किया है तथा उत्पत्ति प्राप्त है के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए दिल्ली की व्यवस्था में सामाजिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास योजना

- नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था -
 - अधिक लगानों स्थापना करना तथा सामाजिक न्याय की स्थापना
 - विदेश नीति में पंचशील का उपनाया गया है -

निदेशक विद्यालयों और मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत -

- नि:मौलिक अधिकार न्याय योग्य है पर निदेशक विद्यालय न्याय योग्य नहीं है

- मौलिक अधिकार राज्य को कुछ विशेष कार्य के लिये देता है, जबकि निदेशक विद्यालयों के कुछ कार्य-कारण का निर्देश देता है -

- मौलिक अधिकारों के मुकाबले में निदेशक विद्यालयों का महत्वपूर्ण है।